मेरा मास्क आपकी रक्षा करता है,

सभी के लिए मास्क
आपका मास्क मेरी रक्षा करता है

सच कहने की ताकत
जालंधर ब्रीज
साप्ताहिक समाचार पत्र

WASH YOUR HANDS
FREQUENTLY
WITH SOAP AND WATER

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 13 JANUARY 2021 TO 19 JANUARY 2021 • VOLUME- 25 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
Low Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD
CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE
E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बॉर्डर पर बीएसएफ को मिली सुरंग, आतंकियों के इस्तेमाल का शक

■ जम्मू/ब्यूरो

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के नीचे एक सुरंग का पता लगाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह एक अभियान के दौरान बीएसएफ के जवानों ने बोबियान गांव में सीमा पार से बनाई गई एक सुरंग का पता लगाया, जिसका निर्माण आतंकवादियों को घुसाने के लिए

किया गया है। बीएसएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा के पांच साल पूरे

कृषि मंत्री बोले- आज हमारी चिंता उत्पादन की नहीं बल्कि सही प्रबंधन की है

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पांच साल पूरे होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को कृषि ही रोजगार प्रदान करता है। उन्होंने आगे बताया कि कोविड के दौरान कृषि क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। आज हमारी चिंता उत्पादन की नहीं है, लेकिन जितना उत्पादन हो रहा है उसका कैसे प्रबंधन करें यह चिंता का विषय है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि खाद्यान के अतिरिक्त दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, बागवानी सभी क्षेत्रों में विश्व में तुलना करें तो हम नबंर-1 पर या फिर नंबर-2 पर होंगे। वैश्विक मानकों के अनुसार हम उत्पादन कर सकें जिससे हमारे कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ सके और हमारे किसान को अच्छी कीमत मिल सके। इस दिशा में भारत सरकार राज्यों के साथ

मिलकर सफलतापूर्वक काम कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक इस योजना से 25 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं, 5 करोड़ नए किसान हर साल जुड़ रहे हैं। 2014-2019 के बीच 1,600 करोड़ रुपए किसानों के प्रीमियम के रूप में जमा हुआ और उनके नुकसान की भरपाई 86,000 करोड़ रुपए देकर की गई। उन्होंने कहा कि अभी तक अगर आप देखेंगे तो 90 हजार करोड़ रुपए किसानों को नुकसान की भरपाई के तौर पर दिए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम बीमा योजना को जितना उत्तम और सुविधाजनक बनाने की इच्छा रखते हैं यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारी कोशिश हो कि देश का हर एक किसान इस बीमा के कवर में आ जाए। इस दौरान उन्होंने कंपनियों को जागरुकता अभियान चलाने की नसीहत दी ताकि दूर-दराज के किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकें।

शहीद हवलदार बलजीत सिंह की पत्नी को मरणोपरांत सेना मेडल से किया गया सम्मानित

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

35 साल के शहीद हवलदार बलजीत सिंह करनाल के गांव डिंगर माजरा के रहने वाले थे। साल 2019 में शहीद हवलदार बलजीत सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। बता दें कि वीरता का यह सम्मान शहीद हवलदार बलजीत सिंह की पत्नी अरुण रानी को बुधवार को परेड के दौरान दिया गया। आपने वीर नारियों को तो देखा

होगा जो अपने वीर पति की ओर से सम्मान प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हैं जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने का विकल्प चुना। क्या आपने कभी दो मौकों पर मरणोपरांत सम्मान पाने वाली वीर नारी देखी है। अगर नहीं तो, आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही गर्व के क्षण के बारे में। हवलदार बलजीत को अक्टूबर 2018 में आतंकवादियों के खिलाफ अपनी शानदार भूमिका के लिए सेना पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया, और फिर फरवरी 2019 में एक सेशन के लिए, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। वीर नारी को इससे पहले अक्टूबर 2018 सेशन के लिए एसएम (जी) से सम्मानित किया गया था और आज शहीद हवलदार बलजीत सिंह की पत्नी ने फरवरी 2019 में अपने पति के सर्वोच्च बलिदान के लिए सम्मान प्राप्त किया।

घाटी में सोशल मीडिया के जरिए आतंक फैलाने की हो रही कोशिश!

सुरक्षा एजेंसियों ने 100 अकाउंट्स का पता लगाया

■ जम्मू/ब्यूरो

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 100 अकाउंट्स का पता लगाया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर एक्टिव हैं। इन अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने के लिए घाटी के युवाओं को उकसाने का प्रयास करते आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगाया गया है, उनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इनका कहीं-न-कहीं जुड़ाव आईएसआई से है। जिन्होंने इस काम के लिए तकनीकी एक्सपर्ट तैनात किया हुआ है।

बता दें कि सुरक्षाकर्मी लगातार आतंकियों की साजिशों को नाकाम कर रहे हैं और घुसपैठियों को निशाना बना रहे हैं। जिसकी वजह से आतंकी संगठनों के इरादों पर पानी फिर रहा है। ऐसे में अब सोशल मीडिया के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर मौजूद एक ऐसे ही अकाउंट के माध्यम से हाल ही में सुरक्षाकर्मियों के कैंप और पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले के निर्देश दिए गए।

दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के स्कूल 18 जनवरी से खोलने के दिए आदेश

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

प्री-बोर्ड तैयारी और व्यावहारिक कार्यों से संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त/ सहायता प्राप्त स्कूल केवल कक्षा 10 और 12 के छात्रों को 18 जनवरी से स्कूल बुला सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि माता पिता की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाना चाहिए। नए साल पर कई राज्यों के स्कूल खुल गए और कुछ खुलने की तैयारी में हैं। बीते 9 महीने से लॉकडाउन और फिर अनलॉक के दौरान बंद रहे स्कूल अब धीरे-धीरे खुलने लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों के लिए हर किसी का यही सवाल रहता है कि दिल्ली में स्कूल आखिर कब खुलेंगे? लोगों के सवाल पर विराम लगाते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्री-बोर्ड तैयारी और व्यावहारिक कार्यों से संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त/ सहायता प्राप्त स्कूल केवल कक्षा 10 और 12 के छात्रों को 18 जनवरी से स्कूल बुला सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि माता पिता की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाना चाहिए।

अटेंडेंस के लिए नहीं होगा इस्तेमाल

दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं इसका रिकॉर्ड को बनाए रखा जाना चाहिए। वहीं इसका उपयोग अटेंडेंस के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना माता-पिता के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक है।

किसान आंदोलन : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पहल का स्वागत तो करते हैं मगर उनका आरोप है कि जो कमिटी किसानों की मांगों को लेकर बनाई गई है वो सरकार के ही पक्ष में काम करेगी। किसानों के संगठनों के प्रतिनिधि और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिन चार लोगों की कमिटी बनाई गई है उन पर किसानों को भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ एक ने कृषि बिल को लेकर सरकार का खुलेआम समर्थन किया है।

सुप्रीम कोर्ट में चली कार्यवाही के बाद दिल्ली की सरहद से फोन पर बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपना आंदोलन जारी

किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे और अपने आंदोलन के स्थल को भी नहीं बदलेंगे

रखेंगे और अपने आंदोलन के स्थल को भी नहीं बदलेंगे। उनका कहना था, हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश और बेंच के दूसरे न्यायाधीशों ने कम से कम आंदोलन कर रहे किसानों की मुश्किलों को तो समझा। सर्वोच्च अदालत ने आंदोलन करने के अधिकार का भी बचाव किया है। ये बहुत बड़ी बात है।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में चिकन की बिक्री पर लगी रोक

दिल्ली में दो नगर निगम ने चिकन की बिक्री और परोसे जाने रोक लगा दी है। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

नई दिल्ली/ब्यूरो

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू की स्थिति को देखते हुए उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दुकानों और रेस्तराओं के चिकन बेचने और रखने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

नगर निगम ने सभी होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को आदेश दिया है कि पोल्ट्री उत्पाद या अंडे ना परोसें वरना उचित कार्रवाई होगी।

एडवायजरी के मुताबिक उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाली सभी मीट की दुकानों, मीट की प्रोसेसिंग इकाइयों, किसी भी अन्य स्थान पर जीवित मुर्गा व मुर्गियां इत्यादि रखने और उनका खरीद-बिक्री करने पर बैन लगाया गया है।

इसमें कहा गया है कि आदेश जनहित में जारी किया गया है और इसका पालन किया जाना चाहिए। दिल्ली में मृत मिले कौओं और बत्तखों के नमूनों में सोमवार को बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने शहर के बाहर से लाए गए प्रसंस्कृत और पैक चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी थी. अधिकारियों ने गाज़ीपुर मुर्गा मंडी को भी बंद कर दिया है।

निगम ने कहा, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाली मांस और पोल्ट्री की दुकानों, मांस प्रसंस्करण इकाइयों के पोल्ट्री या प्रसंस्कृत या पैक चिकन को बेचने या रखने पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। बीते एक सप्ताह में पूर्वी दिल्ली के संजय झील इलाके में कई बत्तखें और शहर के अलग-अलग पार्कों में बड़ी संख्या में कौए मृत मिले हैं।

कमिश्नरेट जालंधर पुलिस ने जालंधर ब्रीज में प्रकाशित खबर का लिया कड़ा संज्ञान

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

जालंधर ब्रीज द्वारा अपने पिछले अंक में पंजाब पुलिस कर्मियों को साल में दो बार अच्छे से ट्रेनिंग देकर आम लोगों से कैसे बोलने के स्कील्स बारे उच्चाधिकारियों का ध्यान केन्द्रित किया गया था ताकि पिछले कुछ महीनों में पुलिस विभाग में तैनात कर्मियों और आम लोगों के बीच किसी कारण विवाद हमेशा सुनने में आता था लेकिन अब विभाग के ए.सी.पी हेडक्वॉर्टर्स बिमलकांत द्वारा पुलिस विभाग के सभी थानों, विंगों और ब्रांचों को लिखती रूप में आदेश जारी किये गए हैं की थानों में आने वाले सभी आम लोगों को बनता सम्मान दिया जाए और अगर किसे थाने के मुंशी या तफतीशी अफसर को किसी केस के संबंध में आम लोगों का फोन आता है तो पहले उन्हें श्रीमान जी या श्रीमती जी कह कर संबोधन किया जाये और उनकी बात को बड़े प्यार से सुन के उनका जल्द समाधान किया जाये ताकि लोगों का पुलिस विभाग और कानून पर भरोसा बना रहे। अब देखना होगा कि पुलिस विभाग के कर्मचारी कब से इन आदेशों की पालना शुरू करते है?

जालंधर ब्रीज के पिछले अंक में छपी खबर

सच कहने की ताकत
जालंधर ब्रीज
हिन्दी समाचार पत्र
• www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

अब क्यों नहीं सुनने को मिलते पंजाब पुलिसकर्मियों की तरफ से श्रीमान और श्रीमती जैसे शब्द

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

पिछले कुछ दिनों से पंजाब पुलिस के कर्मियों को जालंधर में विवादों का सामना करना पड़ रहा है कुछ दिन पहले उनका पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था। ऐसा ही कुछ मामला बाद में पुलिस कर्मियों और वकीलों के बीच कोर्ट परिसर में विवाद देखने को मिला और अब एक दो दिन पहले सत्ताधारी पार्टी के पार्षद के साथ रास्ता न देने के कारण नीयत धरने तक आ गई लेकिन हर बार विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा उन कर्मियों के ऊपर विभागीय कार्रवाई करके हर एक मामले को शांत किया गया। पुलिस विभाग जिस पर लोग इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाए बैठे होते है अगर उनके कर्मचारी लोगों के साथ अच्छे से

तभी पुलिस विभाग और आम लोगों के बीच आपस में तालमेल बढ़ सकता है और अधिकारियों को भी कही विवाद होने पर सड़क जाम और धरने जैसी स्थिति में नहीं पड़ना पड़ेगा

व्यवहार नहीं करेंगे तो लोगों का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठने लगेगा जैसे कुछ सालों पहले श्रीमान जी और श्रीमती जैसे शब्द पुलिसकर्मियों की तरफ से लोगों को सुनने को मिलते थे चाहे वह पुलिस स्टेशन जाए या सड़क पर चैकिंग के लिए पुलिसकर्मी द्वारा रोका जाए उन शब्दों की अब लोगों को कमी महसूस हो रही है।

पिछले कुछ सालों से आपको देखने को मिला होगा की पंजाब सरकार द्वारा काफी पुलिस कर्मियों को प्रमोट करके उच्च पदवी दी गई है। क्या विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों को साल में दो बार अच्छे से ट्रेनिंग देकर बोलने के स्कील्स और फिजिकल फिटनेस जैसे टेस्ट रख कर उनकी काबलियत के तहत उन्हें तैनात नहीं किया जाना चाहिए? तभी पुलिस विभाग और आम लोगों के बीच आपस में तालमेल बढ़ सकता है और अधिकारियों को भी कहीं विवाद होने पर सड़क जाम और धरने जैसी स्थिति में नहीं पड़ना पड़ेगा क्यूंकि जब तक लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास नहीं बढ़ेगा तब तक विवादों के मामले आये दिन आपको सुनने में मिलते रहेंगे।

दखल

शहरी नियोजन और वैकल्पिक ऊर्जा

शहरों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहरी गैस वितरण तंत्र के समांतर अन्य योजनाओं में व्यापक पैमाने पर निवेश करना होगा। सरकार ने प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए नीतिगत स्तर पर कई अहम निर्णय किए हैं। केंद्र सरकार ने 2030 तक अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत से बढ़ा कर पंद्रह प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इय लक्ष्य की पूर्ति से कई समस्याएं स्वत: ही खत्म हो जाएंगी।

झारखंड के कोडरमा शहर के लोगों को जल्द ही रसोई गैस के लिए न तो सिलेंडर की बुकिंग करानी पड़ेगी और न ही उसका इंतजार करना पड़ेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की मंजूरी के बाद वहां शहरी गैस वितरण प्रणाली (सीजीडी) के जरिए गैस पाइप लाइन बिछाने का काम रफ्तार पकड़ रहा है। कोडरमा की तरह ही देश के चार सौ से अधिक गैर-महानगरीय और छोटे शहरों में सीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम प्रगति पर है। किसी भी शहर के विकास को टिकाऊ बनाने के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सबसे प्रमुख कारक होती है। ऊर्जा ही वह संसाधन है, जिस पर हर छोटी-बड़ी मानवीय गतिविधियां टिकी होती हैं। शहरी नियोजन के नजरिए से देखें तो पिछले दो दशक में भारत में शहरीकरण जिस रफ्तार से बढ़ा है, वह अभूतपूर्व है। विश्व आर्थिक मंच की ताजा रिपोर्ट ने पुनः इस बात को दोहराया है कि कई वर्षों तक भारत के विकास की धुरी शहर बने रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की वह रिपोर्ट इसी बात की पुष्टि करती है, जिसमें कहा गया है कि 2050 तक भारत की आधी आबादी शहर केंद्रित हो जाएगी।

यही कारण है कि शहरी नियोजन वर्तमान में सरकार की प्राथमिकता बन गया है। इसे इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि 2004 से 2014 के बीच 1.57 लाख करोड़ रुपए शहरी नियोजन पर खर्च किए गए। जबकि पिछले छह साल में ही 10.57 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट शहरों को व्यवस्थित करने पर खर्च किया जा चुका है। शहरीकरण के विस्तार के साथ ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। हम पहले ही विश्व में ऊर्जा के चौथे बड़े उपभोक्ता हैं। ऐसे में नीति नियोजकों को ऊर्जा की आपूर्ति के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दोहरी जिम्मेदारी को साधना होगा। शहरी नियोजन से जुड़ा यह दायित्वबोध यूरोप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुए गार्डन सिटी मूवमेंट की याद दिलाता है। शहरी नियोजन का यह एक ऐसा अभियान था, जिसके अंतर्गत यूरोप और अमेरिका में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा की आत्मनिर्भरता से युक्त शहर बसाए गए। संयोग से इसी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के जरिए धीरे-धीरे ही सही, कदम बढ़ा रहा है। देश में सीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है।

राज्यों की राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित शहरों में भी शहरी गैस वितरण प्रणाली का प्रस्तावित विस्तार वहां के ऊर्जा अर्थशास्त्र के साथ सामाजिक जीवन को भी स्पंदित कर रहा है। इन प्रयासों से देश के बड़े महानगरों और राज्यों की राजधानी से बाहर सीजीडी का नेवटर्क विकसित होगा, लेकिन इसके लिए हमारे छोटे शहर और वहां के स्थानीय निकाय कितने तैयार हैं, इसकी समीक्षा करनी होगी। शहरी नियोजन के जानकारों की मानें तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के प्रयास शहरों की मौजूदा बुनियादी अवसंरचना को व्यवस्थित किए बिना संभव नहीं हैं। आज शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां अवैध कॉलोनियां और अतिक्रमण की गंभीर चुनौती मौजूद न हो। देश में चंड़ीगढ़, बेंगलुरु, गांधीनगर, पंचकूला, जमशेदपुर, गौतम बुद्ध नगर और नवी मुंबई जैसे शहरों में ऊर्जा की उपलब्धता और उसमें अक्षय ऊर्जा की भागीदारी एक अनुकरणीय पहल है। इन शहरों में किसी भी कम जनसंख्या घनत्व वाले शहर के मुकाबले अधिक हरित क्षेत्र मौजूद है। शहरों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहरी गैस वितरण तंत्र के समांतर अन्य योजनाओं में व्यापक पैमाने पर निवेश करना होगा। इससे शहरों में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए नीतिगत स्तर पर कई अहम निर्णय किए हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 2030 तक अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत से बढ़ा कर पंद्रह प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में अगले गैस के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 66 अरब डॉलर का निवेश प्रस्तावित है। 2016 में प्रारंभ हुई ऊर्जा गंगा जैसी परियोजनाएं इस लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होंगी। हाल ही में बंगाल के उत्तर चौबीस परगना जिले में स्थापित बंगाल का पहला तेल एवं गैस रिजर्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। अशोक नगर तेल एवं गैस रिजर्व से उत्पादन शुरू होने के साथ ही बंगाल भी उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां से तेल निकाला जाता है। शहरी गैस वितरण प्रणाली के अतिरिक्त शहरों को ऊर्जा नियोजन हेतु ठोस अपशिष्ट से बायोमास बनाने की योजना को लोकप्रिय बनाना होगा। महाराष्ट्र और गुजरात में कई सहकारी समितियों ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में ठोस अपशिष्ट से बायोगैस प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित कर ऊर्जा आत्म निर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। शहरों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का विचार नया नहीं है। कई देश इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन और जर्मनी जैसी महाशक्तियां ही नहीं, तेल से संपन्न सऊदी अरब जैसे देश भी प्रभावी कदम बढ़ा चुके हैं।

सऊदी अरब में तो बकायदा नियोम नामक एक ऐसा शहर बसने जा रहा है, जो हाइड्रोजन इकोनॉमी और अक्षय ऊर्जा संसाधनों से पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को अलग कर तैयार होने वाला कार्बन मुक्त ईंधन हमारे शहरों में एक नई परिवहन क्रांति ला सकता है। केंद्र सरकार इसी क्रम में देश में ग्रीन सिटी की अवधारणा को भी प्रोत्साहित कर रही है। ये ऐसे शहर होंगे, जो ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी तरह अक्षय ऊर्जा संसाधनों से पूर्ण करेंगे। ग्रीन सिटी में घरों में सौर ऊर्जा के अनुप्रयोग बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देने की कार्ययोजना को नया रूप दिया जा रहा है। इस तरह शहर के बाहर सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे।

नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय की योजना के अनुसार फिलहाल हर राज्य में एक ग्रीन सिटी स्थापित करने की तैयारी है। हमारे नीति निर्धारकों को शहरी और ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को गढ़ते समय उसे ऐसा स्वरूप देना होगा, जिससे वे एक-दूसरे के पूरक बनें। केंद्र सरकार ने हाल ही में एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी देने की योजना है। इससे एथेनॉल उत्पादन में लगे छोटे और मझोले उद्योगों को तो राहत मिलेगी ही, गन्ना किसानों को भी अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। वैसे तो एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। जाहिर है, ऐसी योजनाओं से शहर और ग्रामीण भारत के बीच ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तैयार करने के प्रयास भी मजबूत होंगे। विकास की कोई भी योजना आर्थिक संसाधनों के बिना सफल नहीं हो सकती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हमने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से बड़े-बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं। हाल ही में देश के नौ बड़े नगर निगमों ने म्यूनिसिपल बांड जारी करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे छोटे शहर ऊर्जा समेत अपनी दूसरी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक संसाधन जुटा सकेंगे। अगर हम शहरों का नियोजन करते समय ऊर्जा के विविध रूपों की स्थानीय स्तर पर उत्पादकता के साथ उपलब्धता के प्रयासों को प्राथमिकता देंगे, तो इसका लाभ शहर ही नहीं, हमारी भावी पीढ़ियों के साथ पर्यावरण को भी मिलेगा।

विचार

जहरीली शराब से फिर मौतें

मप्र के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब से मरने का यह पहला मामला नहीं है। आए दिन किसी न किसी राज्य से इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक कब लगेगी।

मध्यप्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सात लोग मानपुर तहसील के पृथ्वी गांव और छेरा गांव के हैं जबकि तीन लोग सुमावली के पावली गांव के हैं। घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। प्रशासन स्थिति को संभालने में लगा है। यह घटना बताती है कि प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस तो आंखें मूंदे हुए हैं और किसी पर भी कार्रवाई कर पाने में लाचार है। हमेशा से होता यही आया है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो रस्मी तौर पर कुछ अधिकारी-कर्मचारी निलंबित किए जाते हैं और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देकर पिंड छुड़ा लिया जाता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई किसी पर नहीं होती, जिससे कोई सबक ले सके। वही अब भी हुआ है। जहरीली शराब का कारोबार करने वालों का जाल काफी बड़ा है। जिस तरह यह धंधा चलता आ रहा है उससे तो लगता है कि यह व्यवस्था का हिस्सा बन गया है।

जहरीली शराब ही क्यों, इस तरह के कई अवैध कारोबार होते हैं जिनके बारे में सरकारें, प्रशासन और पुलिस सब जानते हैं, लेकिन उन पर लगाम नहीं लगाते। यह कोई छिपी बात नहीं है कि अवैध शराब का धंधा स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ही चल पाता है। कच्ची शराब का सेवन आमतौर पर निचले तबके के लोग करते हैं, क्योंकि यह सस्ती होती है और आसानी से मिल जाती है। इसलिए निम्न-वर्गीय बस्तियों, झुग्गी बस्तियों में कच्ची शराब के मटके ज्यादा चलते हैं। पाउचों तक में शराब बिकती है। ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर चलता है। पर पुलिस और प्रशासन इन्हें इसलिए चलने देता है, क्योंकि ये धंधे उगाही के बड़े स्रोत होते हैं। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसे रफा-दफा कर दिया जाता है और थोड़े दिन बाद फिर से धंधा शुरू हो जाता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन कठघरे में आएगा ही।

यह कोई पहला मौका नहीं है जब जहरीली शराब के कारण इतनी मौतों की खबर आई हो। मगर पिछली घटनाओं से भी कोई सबक नहीं लिया जाता। अगर सरकार ठान ले तो जहरीली शराब बेचने वालों का सफाया करना कोई मुश्किल काम नहीं है! मुरैना की यह घटना बताती है कि प्रशासन अगर सचेत रहता तो शायद यह हादसा टल सकता था। इस हादसे ने सरकारी तंत्र की लापरवाही को उजागर कर दिया है। शराब के अवैध कारोबार को रोकने का पहली जिम्मेदारी आबकारी विभाग की विभाग की होती है। जाहिर है, इस महकमे ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, वरना जहरीली शराब कहां से आ रही है और कहां बन रही है, इसका समय रहते पता चल सकता था। कच्ची शराब सस्ती होती है और आसानी से मिल जाती है, इसलिए निम्न-वर्गीय बस्तियों में कच्ची शराब के मटके ज्यादा चलते हैं। पुलिस और प्रशासन इन्हें इसलिए चलने देता है, क्योंकि ये धंधे उगाही के बड़े स्रोत होते हैं।

आदिवासियों की सुध लेनी होगी

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2011-12 के मुताबिक दिल्ली की कुल आबादी का ढाई फीसद हिस्सा आदिवासियों का है। सवाल है कि अतीत को ढोते दिल्ली की आबादी के ढाई फीसद आदिवासियों को विकास के मॉडल में शामिल किए जाने की कोई मंशा दिल्ली सचिवालय की है या फिर बदनामी के अंधेरे खोखल में अतीतजीवी बने रहना उन आदिवासियों की नियति है? जो भी हो, अब बदलाव की सूरत दिखनी ही चाहिए।

दिल्ली नहीं मानती कि उसके दामन में कोई आदिवासी रहता है। लिहाजा राज्य सरकार की विकास प्राथमिकता में वहां के आदिवासियों को लेकर कोई कार्ययोजना ही नहीं है। सवाल है कि क्या राज्य सरकार के पास आदिवासी आबादी न होने के इस निष्कर्ष का कोई पुख्ता प्रमाण है या नौकरशाह खुद इसे मान चुके हैं? जैसे विभाजन के समय पाक और बाद में देश के मुख्तलिफ इलाकों से पलायन कर कई नस्लों और जाति-प्रजातियों के लोग आकर यहां बसते गए, उसी तरह वे लोग नहीं आए जो नस्लीय पूर्वाग्रह या विकास की चपेट से उजड़े या उखड़े लोग थे, जो आदिवासी थे। सच यह है कि दफ्तरशाही की गलतफहमी के चलते पहाड़ों और जंगलों से आए लाखों लोग 'आदिवासी' की पहचान से मुक्त होकर दिल्ली में रहते हैं, जबकि उनके पूर्वजों-पुरखों को इतिहास के पुरालेखों में आदिवासी कहा गया है।

पुरालेखों और प्रमाणों पर नौकरशाही माथापच्ची नहीं करना चाहती। झारखंड में अगरिया समुदाय दशकों से आदिवासी कहलाने को तरस रहा है। वे प्राचीन लौहशिल्पी हैं, हैमेटाइट पत्थरों से लोहा निकालने का काम कई युगों से करते चले आ रहे हैं। इस जनजाति का पूरा नाम असुर अगरिया है, लेकिन झारखंड के सरकारी अभिलेखों में इनका उल्लेख 'अगरिया' के रूप में किया गया है। लिहाजा, वे अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वनीधिकार अधिनियम, 2006 के तहत विशेषाधिकारों का खालिस लाभ चाहते हैं। चूंकि जिलाधिकारियों ने उन्हें आदिवासी प्रमाण-पत्र ही जारी नहीं किया, इसलिए वे अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। 2003 में सरकार की अधिसूचना के बाद छत्तीसगढ़ में अगरियों को पहले ही आदिवासी का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी इस पर अमल नहीं किया है। यही स्थिति पूर्वोत्तर भारत के कोच, राजबोंग्सी, ताई अहोम, मटक और मोरन समुदायों की है, जो आदिवासी कहलाने को तरस रही हैं।

दिल्ली में भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी संजातीय और नस्लीय पहचान के लिए तरस रहा है। वैसे तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2011-12 के मुताबिक दिल्ली की कुल आबादी का ढाई फीसद हिस्सा आदिवासियों का है। इन समुदायों ने खानाबदोश खासियत को लेकर इतिहास में भली-बुरी पहचान बनाई है। इस बारे में फिलिप मिडोज टेलर (कॉन्फेशन ऑफ ए ठग/ 1939) लिखते हैं कि 'लूटपाट की उनकी जीवन-पद्धति ने उन्हें इतना खूंखार बना दिया कि एक राज्य दूसरे राज्य को परेशान करने के मकसद से इन आपराधिक तबियत और हरकतों को अंजाम देने वाले आदिवासियों का सहारा लेते थे। यानी पड़ोसी राज्य के राजा-रजवाड़ों के इशारे पर वे आपराधिक आदिवासी राहजनी करते थे। उन अपराधजीवी नस्लों को रजवाड़ों ने संरक्षण दिया तो लूट का एक बड़ा हिस्सा राजकोष में भरा जाने लगा।' हद तो तब हो गई जब इन अपराधी नस्लों ने बर्बरता की हदों के पार जाकर हत्या का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट अस्तित्व में आया। दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले कोई दर्जन भर आदिवासी समुदाय इसी अमानवीय सूची में शुमार किए गए।

क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के तहत सैकड़ों समुदायों पर अपराधी नस्ल का ठप्पा लगाया गया। उसके बाद इस कानून की आड़ में केंद्र सरकार के कपट भरे कठोर व्यवहार की शुरुआत हुई। इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी बने सांसी लोग, जो आज भी दिल्ली में रहते हैं। अंग्रेजों के गजटों-गजेटियर में उन तमाम आदिवासी समुदायों के नाम लिखे और वे 'अपराधी कबीले' या सरकश जनजाति घोषित किए गए। लिहाजा, पुलिसिया दमन से परेशान इनके मर्द या तो जंगलों में रहते थे या पकड़े गए तो जेलों में- नतीजतन, औरतें शराब की भट्ठियों में रहती थीं या समाज के चौधरियों के हरम में या सत्ता के बिछौने पर। बावरिया, सांसी और बंजारा समुदायों को लेकर समाज जहां चौकन्ना और सतर्क था वहीं गाड़िया लोहार अपने लौह-कर्म से मुख्य धारा के साथ सहज होकर जीवनयापन करते रहे। यहां तक कि खुली बाजार-व्यवस्था के पहले तक जब दिल्ली का दायरा आज के मुकाबले कम था, तो ये कलंदर-मदारी-नट और संपेरों की कलाबाज और कारीगर जनजातियां आसपास बस्तियों में डेरा जमा कर अपने परिवार का भरण-पोषण करतीं थीं। बीती सदी के अंत तक दिल्ली की कच्ची बस्तियों में डेरा डाल कर पुरखों से संपेरे सांपों का तमाशा दिखा कर, बहेलिए चिड़ियों का शिकार कर और कलंदर बंदर-भालू नचा कर अपना पेट भरते थे।

पर जमाना बदला, तो माहौल बदला। यह बदलाव वाजिब था। बल्कि कानून के प्रावधानों और उन प्रावधानों की पेचीदगी ने जैसे वक्त के पहिए को रोक दिया। वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 से अस्तित्व में था, मगर 1990 में इसे सख्ती से लागू कर मदारी-कलंदर और संपेरों के पेशे पर रोक लगा दी गई। वन्य-जीवों को बचाने की मुहिम की व्यावहारिक और वाजिब जरूरत महसूस की गई। लिहाजा, दिल्ली की उन अनियमित बस्तियों में विभिन्न प्रजाति के सांपों के रखने की मनाही हो गई। मदारियों और कलंदरों का बंदर-भालू तमाशा थम गया। बहेलियों के तीर-कमान और गुलेल की मार का कौशल इतिहास की कंदराओं में जा सिमटा। ऐसे में हजारों मदारी-कलंदर और बहेलिए भीख मांगने को मजबूर हुए। मगर कोई इकतीस साल पुराना भिक्षावृति निवारण कानून रोजी-रोटी के उनके वैकल्पिक उपाय में अड़चन बना। भिक्षावृति निवारण कानून की परवाह किए बगैर ये जनजातियां दिल्ली और उसके समीपवर्ती उपनगरों की सड़कों पर सक्रिय हो गईं।

सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि भूख ने उन्हें इतना समझौतावादी बना दिया कि इस जनजातीय समाज की लड़कियों की वजह से राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाके 'हॉट बेड ऑफ दिल्ली' के नाम से चिह्नित और चर्चित हुए। इन मदारियों-कलंदरों-संपेरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए राष्ट्रीय राजधानी के नागरिक संगठनों ने दिल्ली सचिवालय से लेकर मंत्रालयों की देहरी पर नाक रगड़ी और गुजारिशें की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यह सच है कि दिल्ली के समीपवर्ती इलाकों के लुटेरे बावरिया और यहां के विभिन्न इलाकों में रहने वाले सांसी जनजाति लंबे समय से विधि-व्यवस्था को चुनौती देते रहे हैं। उनके आपराधिक चरित्र ने दिल्ली को बहुत अस्त-व्यस्त किया। दिल्ली में रहने वाला आज का प्रमुख जनजातीय समाज सांसी भले अतीत में अपराधजीवी रहा है और यह भी सत्य है कि हाल के वर्षों तक दिल्ली पुलिस के लिए सांसी सिरदर्दी रहे हैं। मगर हालात बदले हैं। उन्हें आपराधिक अतीत का अपराधबोध भी है, लेकिन सिविल सोसाइटी इस धारणा से मुक्त नहीं हो पाया है कि सांसियों में मुक्ति की छटपटाहट है। समाज का यह पूर्वाग्रह बहुत स्वाभाविक है, जो किसी कानून और उसकी बाध्यता की जोर-आजमाइश से मिटाया नहीं जा सकता। अपराध से उपजे आतंक से ग्रस्त समाज का इंद्रियबोध और अपराध से लोहा लेती सरकार की चेतना इतनी सुस्त और गंदली होती है, जो सुधार के लिए तत्पर किसी अपराधी पर मेहरबान होने में झिझक रखती है, बल्कि ऐसी चर्चाओं से भड़कती भी है।

ट्विटर

मुरैना के हादसे से सरकार दुखी है। जिन लोगों ने जान गंवाई है, सरकार उनके परिजनों के साथ है। जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

सरकार को लोगों की भलाई की चिंता नहीं है। उसे सिर्फ अपनी ब्रांडिंग की फिक्र है। प्रदेश की जनता परेशान है और सरकार वाहवाही लूटने में जुटी है।

कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री

सत्यार्थ

ऊंचे आदर्श अपनाएं

अपने जीवन काल में 52 ग्रंथों की रचना करने वाले और भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वावलंबन व सादगी के प्रतीक थे। एक बार विद्यासागर को इंग्लैंड में एक सभा की अध्यक्षता करनी थी। उनके बारे में यह मशहूर था कि उनका प्रत्येक कार्य घड़ी की सुई के साथ पूर्ण होता है। वे लोगों से भी यही अपेक्षा रखते थे कि वे अपना कार्य समय पर करें। विद्यासागर जी जब निश्चित समय पर सभा भवन पहुंचे तो देखा कि लोग बाहर घूम रहे हैं। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि सफाई कर्मचारियों के न आने की वजह से अभी भवन की सफाई नहीं हुई है। यह सुनते ही विद्यासागरजी ने बिना देर किए झाड़ू उठाई व सफाई शुरू कर दी। उन्हें ऐसा करते देख बाकी लोगों ने भी सफाई करना शुरू कर दी। देखते ही देखते भवन साफ हो गया और सारा फर्नीचर यथास्थान लगा दिया गया। जब सभा आरंभ हुई तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने संबोधन में कहा-कोई व्यक्ति हो अथवा राष्ट्र, उसे स्वावलंबी होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा कि एक-दो व्यक्तियों के न आने से हम सभी परेशान हो रहे थे। संभव है कि उन लोगों तक इस कार्य की सूचना न पहुंची हो या फिर किसी अन्य वजह से वे यहां न पहुंच सके हों। क्या ऐसी दशा में आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाता? यदि ऐसा होता तो कितने लोगों का आज का श्रम व समय व्यर्थ हो जाता। सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए और वक्त पड़ने पर किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति भी जीवन में उच्च आदर्श अपनाकर किस तरह महानता को प्राप्त करता है, विद्यासागरजी का जीवन हमें यही सिखाता है।

फरीदाबाद में लोहिड़ी पर्व की खुशी

मकर संक्राति और लोहिड़ी पर्व के नजदीक आते ही देशभर में तैयारिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और युवाओं ने पर्व मनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में मंगलवार को फरीदाबाद में एक महिला संस्थान की छात्राओं ने लोहड़ी का त्योहार मनाया।

जापान के दो और क्षेत्रों में आपातकाल स्थिति की संभावना

टोक्यो, (एजेंसी)। जापान के दो और जिलों आइची और गिफू में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार के बीच आपातकाल स्थिति शुरू होने की संभावना जताई गई है। क्योदो समाचार एजेंसी ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। जापानी मीडिया ने सोमवार को बताया कि पिछले सप्ताह घोषित आपातकाल टोक्यो, कनागावा, सैतमा और चिबा के अलावा तीन और शहरों ओसाका, क्योटो और योगो तक बढ़ाया जा सकता है। समाचार एजेंसी की मंगलवार की रिपोर्ट में बताया गया कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने ओसाका, क्योटो और योगो में आपातकालीन स्थिति की पुष्टि की है, जो बुधवार से शुरू हो सकती है। एजेंसी के अनुसार सरकार ने आइची और गिफू क्षेत्रों में भी आपातकाल लगाने का मन बना लिया है और यह संभवतः ओसाका, क्योटो और योगो के साथ ही लगाया जाएगा।

सेना किसी भी खतरे से निपटने को तैयार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए शक्तिशाली खतरा पैदा करते हैं और टकराव की आशंका को दूर नहीं किया जा सकता।

उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हम आतकंवाद के लिए जीरो-टोलरेंस रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सही समय आने पर हम इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। सीमा पर देशों के लिए ये एक साफ संदेश है। उन्होंने वस्तुतः भारतीय सेना द्वारा पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थिति कुछ रणनीतिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कब्जा किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि सेना देश के हितों और लक्ष्यों के अनुरूप पूर्वी लद्दाख में अपनी स्थिति कायम रखेगी।

उत्तरी सीमाओं को दोबारा संतुलित करने की आवश्यकता

सेनाध्यक्ष ने कहा कि उत्तरी सीमाओं को दोबारा संतुलित करने की आवश्यकता है और हमने इसे लागू किया है। जब तक हम राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमने पूरी तैयारी की हुई है। सेनाध्यक्ष ने कहा कि एलएसी के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में घर्षण बिंदू हैं, जहां चीन ने बुनियादी ढांचे का विकास किया हुआ है। हमने इन चुनौतियों का सामना किया और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ लद्दाख ही नहीं, बल्कि पूरे एलएसी पर उच्च स्तर की निगरानी की हुई है। कोर कमांडर स्तर के आठवें दौर की बातचीत हो चुकी है, अब 9वें दौर की वार्ता का इंतजार है। सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमें बातचीत के लिए जरिए समाधान निकालने की उम्मीद है।

सेना ने सर्दियों की कर ली है पूरी तैयारी

सेनाधयक्ष ने कहा कि सेना ने सर्दियों की पूरी तैयारी कर ली है। एमएम नरवणे ने कहा कि हम शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद करते हैं। बीते साल में सबसे मुख्य चुनौती कोविड-19 और उत्तरी सीमाओं पर की स्थिति रही। सेनाध्यक्ष ने जानकारी दी कि हमने उत्तरी सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई, हम शांति की बहाली की उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर कोई घटना होगी, तो उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। इसके अलावा सेनाध्यक्ष ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोद्योगिकी सक्षम सेना विकसित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसमें सभी नई तकनीकी को शामिल करने पर जोर दिया

जवानों में तनाव कम करने लगातार कर रहे हैं प्रयास

इसके अलावा सेनाध्यक्ष नरवणे ने कहा कि जवानों में तनाव को लेकर यूएसआई की रिपोर्ट में सैंपल साइज काफी कम था। रिपोर्ट में सैंपल साइज 400 था, जबकि मेरा मानना है कि 99 फीसदी स्पष्टता के लिए सैंपल साइज 19,000 होना चाहिए। हम जवानों में तनाव कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में जवानों की आत्महत्या करने के मामलों में कमी आई है।

न्यूज

जहरीली शराब मामले में फरार आरोपियों पर इनाम घोषित

बुलंदशहर, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के जीत गढ़ी में जहरीली शराब पीने से हुई छह लोगों की मृत्यु के मामले में पुलिस ने अभी तक अवैध शराब के धंधे में लिप्त 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि वांछित चल रहे चार लोगों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह नेबताया कि जहरीली शराब पीने से पिछले दिनों जीत गढ़ी गांव में छह लोगों की मृत्यु हो थी, जबकि कई लोगों का अभी भी अस्पतालों में इलाज हो रहा है। पुलिस ने गांव में अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा करने वाले कुलदीप को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब तक इस धंधे में लिप्त नौ और आरोपियों गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि चंद्रभान उर्फ मिंकु, टिंकू उर्फ टीकम सिंह और यादराम फरार चल रहे हैं।

भारत-बांग्लादेश के पुलिस बलों के बीच और बढ़ेगा सहयोग

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत और बांग्लादेश के पुलिस बलों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तहत वैश्विक आतंकवादी संगठनों तथा भगोड़ों के खिलाफ एकजुट होकर अभियान चलाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के पुलिस बलों के प्रमुखों के बीच मंगलवार को पहले प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वर्चुअल संवाद के दौरान यह सहमति बनी। दोनों पक्षों के बीच यह संवाद सकारात्मक और भरोसे के माहौल में संपन्न हुआ। बैठक में मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग, पारस्परिक चिंता के मुद्दों को और आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार-विमर्श करते हुए दोनों देशों के पुलिस बलों के संबंधों को अधिक मजबूत बनाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि बदलती सुरक्षा और आतंकवाद रोधी चुनौतियों से समयबद्ध और प्रभावी रूप से निपटने कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट 'नोडल बिंदुओं' की स्थापना की जाएगी।

असम में दिखने लगा विपक्षी दलों के बीच बिखराव

मॉस्को, (एजेंसी)। निवर्तमान नई दिल्ली, (एजेंसी)। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के विपक्षी दलों में बिखराव दिखने लगा है। हाल ही में बोडो काउंसलिंग के चुनाव मिलकर लड़ने वाले कांग्रेस और एआईयूडीएफ में दूरियां बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि वह बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ)के साथ चुनाव लड़ने से प्रदेश में ध्रुवीकरण के संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए कांग्रेसी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट 41.9 प्रतिशत मिले थे तो वहीं कांग्रेस को मिलाकर 44 प्रतिशत। विपक्षी पार्टियां अलग-अलग लड़ी थी, इसलिए भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन के बाद राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में मतभेद हैं। प्रदेश अध्यक्ष रिपुण बोरा से अधिकतर नेता नाराज हैं। गौरव गोगोई और सुष्मिता देव अभी इतने परिपक्व नहीं हैं।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे! कोरोना वायरस से सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही बचाव हैं। कोरोना को धोना हैं।

कॉलोनी में कुत्ता घुमाने पर टोकती थी महिला

पड़ोसी ने एसडीएम की बहन को गला घोंटकर मार डाला

जयपुर, (एजेंसी)। शहर में मामूली बात पर बेरहमी से शिक्षिका की हत्या की खबर से कोहराम मचा हुआ है। यहां सोमवार करीब सुबह 8.30 बजे आरएएस अफसर की बहन की हत्या कर दी गई। शिप्रापथ थाना पुलिस को मामले में मृतिका के पड़ोसी युवक पर शक हुआ तो उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। कड़ाई से हुई पूछताछ में उसने बताया कि सोमवार की सुबह कॉलोनी में कुत्ता घुमाते समय उसकी कहासुनी पड़ोस में रहने वाली 55 वर्षीय विद्या देवी से हो गई थी। वह अक्सर कॉलोनी में कुत्ता घुमाने के लेकर रोक-टोक करती थीं, इसलिए उसने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी।

रोका-टोकी से था नाराज: एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने सोमवार रात 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी की पहचान 20 वर्षीय कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। वह 12वीं का छात्र है। बदला लेने के इरादे से वह विद्या देवी के घर में घुसा और उनका बेरहमी से गला घोंट डाला।

आरोपी पुलिस को करना चाह रहा था गुमराह

आरोपी इतना चालाक था कि हत्या को लूट की घटना दिखाने के लिए उसने मृतिका के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद उसने दुपट्टे से उनके शव को रेलिंग से बांध दिया। हत्या के बाद वह मृतिका का मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान भी साथ ले गया था। जब आसपास के लोगों ने देखा कि विद्या देवी का शव उनके घर की रेलिंग से बंधा हुआ है तब उसी दिन सुबह करीब पौने 10 बजे पुलिस को सूचना दी गई।

100 पुलिसकर्मियों ने कॉलोनी के हर घर में की पूछताछ

मामले की जांच के लिए पुलिस की 10 टीम शिप्रापथ कॉलोनी में पहुंची। इन 10 टीमों के 100 पुलिसकर्मी कॉलोनी के हर घर में पूछताछ के लिए पहुंचे। जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले कृष्ण कुमार के चेहरे पर खरोंच का निशान देखा। पूछताछ में उसने बताया कि वह कुत्ते खिलाता है, जिसका पंजा उसके चेहरे पर लग गया है। वहीं, लोगों ने बताया कि सोमवार की सुबह कृष्ण कुमार और विद्या देवी के बीच कुत्ते को लेकर विवाद हुआ था। संदेह होने पर पुलिस उसे थाने ले गई, जहां उसने सच उगल दिया।

घर में अकेली रहती थीं विद्या देवी

कमिश्नर ने बताया कि विद्या देवी जयपुर में एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाती थीं। उनके पति का देहांत हो चुका था। उनके बेटे अभिनव चतुर्वेदी भोपाल के एक आईटी कंपनी में प्रोडक्शन इंजीनियर हैं। इसके अलावा उनके छोटे भाई युगांतर शर्मा आरएएस अफसर हैं। वे जयपुर में एसडीएम हैं। ऐसे में विद्या देवी शिप्रापथ स्थित अपने घर में अकेली रहती थीं।

देश के कई शहरों में पहुंची कोविशील्ड

पूनावाला बोले- कई देशों ने पत्र लिखकर मांगी वैक्सीन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप दिल्ली समेत 14 शहरों में पहुंच गई है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का कहना है कि सरकार के विशेष अनुरोध पर हमने पहली 10 करोड़ खुराकों की कीमत 200 रुपए प्रति खुराक (जीएसटी अतिरिक्त) रखी है। वो भी इसलिए क्योंकि सरकार पहले कमजोर, गरीब, स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने वाली है। पूनावाला ने कहा कि बाद में हम वैक्सीन निजी कंपनियों को एक हजार प्रति खुराक पर बेचेंगे। पूनावाला ने कहा कि हम हर महीने 7-8 करोड़ खुराक बनाते हैं।

अदार पूनावाला ने कहा कि हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना होगा, इसलिए इसमें लाभ नहीं देख रहे हैं। कई देश प्रधानमंत्री कार्यालय को सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की सप्लाई के लिए पत्र लिख रहे हैं। हम सभी को खुश रखना चाहते हैं। अदार पूनावाला ने कहा कि हम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम हर जगह

16 को देश में टीकाकरण अभियान शुरू

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक ने कोरोना वायरस के टीके के निर्माण एवं वितरण के संदर्भ में मंगलवार को एक संसदीय समिति के समक्ष जानकारी दी और सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति की बैठक उस समय हुई है जब देश में आगामी 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान आरंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम करार दिया है। इस अभियान में करीब तीन करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी।देश में कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आरंभ करते हुए 16 जनवरी को टीकाकरण मुहिम की शुरुआत से चार दिन पहले 'कोविशील्ड' टीकों की पहली खेप मंगलवार सुबह पुणे से दिल्ली पहुंची। 'स्पाइजेट' का विमान सुबह करीब आठ बजे पुणे हवाईअड्डे से रवाना होने के बाद टीकों के साथ सुबह करीब 10 बजे दिल्ली हवाईअड्डे पहुंचा।

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को लेकर प्रतिनिधि सभा में आज होगा मतदान

वाशिंगटन, (एजेंसी)। कैपिटल बिल्डिंग (अमेरिकी संसद भवन) पर पिछले हफ्ते हुए हिंसक हमले के मद्देनजर अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर डेमोक्रेटिक नेताओं के नियंत्रण वाली अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बुधवार को मतदान होगा।

सांसदों जैमी रस्किन, डेविड सिसिलिने और टेड लियू ने महाभियोग का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे प्रतिनिधि सभा के 211 सदस्यों ने सह-प्रायोजित किया। इसे सोमवार को पेश किया गया था। सदन में बहुमत के नेता स्टेनी होयर ने अपने पार्टी सहकर्मियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा कि महाभियोग को लेकर मतदान बुधवार को होगा। इस प्रस्ताव में निर्वतमान राष्ट्रपति पर अपने कदमों के जरिए छह जनवरी को राजद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग (संसद परिसर) की घेराबंदी के लिए तब उकसाया, जब वहां इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी और लोगों के धावा बोलने की वजह से यह प्रक्रिया बाधित हुई।

राजनीतिक दलों के चुनाव के लिए प्रक्रिया पर विचार करे ईसीआई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए आदर्श प्रक्रिया बनाने और इसे देश के सभी दलों के संविधान में इस प्रक्रिया को शामिल करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने आयोग को इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को बतौर प्रतिवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

चीफ जस्टिस डीएन पटेल तथा जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने निर्वाचन आयोग को इस याचिका पर निर्णय लेने को कहा है। साथ ही बेंच ने वकील सी. राजशेखरन की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया है। याचिकाकर्ता राजशेखरन अभिनेता कमल हासन के राजनीतिक दल मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। राजशेखरन की ओर से वकील अभिमन्यु तिवारी ने बेंच के समक्ष कहा कि राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव में आयोग के विनियामक निरीक्षक का अभाव है। निर्वाचन आयोग ने 1996 में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों को पत्र जारी किया था और इसमें कहा गया था कि वे संगठनात्मक चुनावों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं।

मिशन 2022 में जुटी आम आदमी पार्टी

यूपी में केजरीवाल ने उतारी 40 विधायकों की फौज

पंचायत चुनाव में भी दिखेगा दम

लखनऊ, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के तेवर इस बार बदले-बदले लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार पार्टी वाकई में यूपी में राजनीति को लेकर गंभीर है। उसके बड़े-बड़े नेता उत्तर प्रदेश के लगातार दौरे कर रहे हैं। दौरे के समय बखेड़ा भी खड़ा हो रहा है। मसलन सोमनाथ भारती पर स्याही फेंक दी गई। लगता है ऐसी राजनीतिक जंग जारी रहने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 40 विधायकों की फौज यूपी में उतार दी है। पार्टी का असली लक्ष्य 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। इसके अलावा प्लान ये भी है कि होली के बाद एक बड़ी रैली की जाए, जिसमें अरविंद केजरीवाल चुनावी बिगुल फूंकें।

आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले ही ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले दिल्ली विधानसभा के विधायक वहां (यूपी) अपना फोकस बढ़ाएंगे, लेकिन लंबे वक्त बाद ये अब हो रहा है। पार्टी ने अपने 35-40 विधायकों को यूपी के मैदान में उतार दिया है। ये सभी विधायक या तो यूपी के रहने वाले हैं या फिर दिल्ली में यूपी वालों की राजनीति करते हैं। ऐसे विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है कि क्षेत्र में घूम-घूमकर लोगों से संपर्क बढ़ाएं। उनको पहला टारगेट पंचायत चुनाव का दिया गया है। मार्च में होने जा रहे पंचायत चुनावों में जिला पंचायत के लिए पार्टी उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। ऐसे में ये सभी विधायक जिताऊ कैंडिडेट खोजेंगे और उनकी जीत के लिए दमखम लगाएंगे। आम आदमी पार्टी ने जिन विधायकों की यूपी में ड्यूटी लगाई है, उनमें सोमनाथ भारती, नरेश यादव, अखिलेश पति त्रिपाठी, पवन शर्मा और अजेश यादव का अहम रोल रहने वाला है।

आतंकवाद पर पाकिस्तान को बचाने की जुगत में चीन

सुरक्षा परिषद समितियों में रोका भारत का रास्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताकतवर टेबल पर भारत की मौजूदगी भी चीन को खटकने लगती हैं। खासकर ऐसे में जबकि भारत अस्थाई सदस्य के तौर पर सुरक्षा परिषद की नई अहम कमेटियों की अध्यक्षता का भी दावेदार हो। यही वजह है कि चीन ने आतंकियों को प्रतिबंधित सूची में डालने वाली अलकायदा सेंक्शन कमेटी की अध्यक्षता पर अडंगा लगाया।

हालांकि जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद में शरीक भारत आतंकवाद निरोधक मामलों और लीबिया व तालिबान संबंधी मसलों की कमेटी की अध्यक्षता करेगा। दरअसल, सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों के लिए क्रमिक अध्यक्षता का प्रावधान है, साथ ही परिषद के मातहत काम करने वाली विभिन्न कमेटियों में अस्थाई सदस्यों को भी अगुवाई का मौका दिया जाता है।

चीन अकेला ऐसा मुल्क था जिसने इसका विरोध किया

बीते दिनों जब भारत के आतंकवाद विरोधी मामलों को देखने वाली और आतंकवादियों एवं आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध तय करने वाली अल कायदा सेक्शन कमेटी की अध्यक्षता का मामला आया तो चीन अडंगा लगाने से बाज नहीं आया। चीन अकेला मुल्क था, जिसने इसका विरोध किया। ऐसे में अध्यक्षता नॉर्वे को दी गई। हालांकि भारत आतंकवाद निरोधक मामलों संबंधी समिति की अध्यक्षता करेगा। चीनी विरोध के कारण यह पहला मौका है, जब सुरक्षा परिषद की तालिबान एवं अल कायदा संबंधी उप समितियों की अध्यक्षता अलग-अलग देशों के पास होगी। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अगले साल भारत के पास अल-कायदा संबंधी प्रतिबंध समिति की अगुवाई आ सकती है।

भारत के रास्ते में अडंगा लगाने के पीछे चीन को थी ये चिंता: भारत के रास्ते में अडंगा लगाने के पीछे चीन की चिंता अपने चहेते पाक को बचाने की थी, जो आतंकियों की बड़ी पनाहगाह है। हालांकि सुरक्षा परिषद में कामकाज के तरीकों से वाकिफ जानकारों का मानना है कि उप समितियों का अध्यक्ष बनने से फर्क नहीं पड़ता, चूंकि भारत ने हाफिज सईद एवं मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सुरक्षा परिषद से बाहर रहते प्रतिबंधित सूची में डलवाया था।

अकाट्य सबूतों के आगे चीन को भी झुकना पड़ा: चीन ने मसूद अजहर जैसे आतंकी को बचाने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जैसे पी-5 देशों की तरफ से पेश प्रस्ताव का रास्ता रोका, यह पूरी दुनिया ने देखा। मगर आखिरकार भारतीय दलीलों और पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अकाट्य सबूतों के आगे चीन को भी झुकना पड़ा। जानकारों के मुताबिक परिषद के क्रमिक अध्यक्ष या कमेटी के प्रमुख के तौर पर किसी भी देश के पास अपने कार्यकाल के दौरान बैठकें बुलाने और उनका एजेंडा तय करने का अधिकार है, लेकिन परिषद के फैसले का रुख इससे प्रभावित हो यह जरूरी नहीं है।

सियासत — उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में एक सीट के लिए होगा घमासान

भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर

लखनऊ, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों के लिए सोमवार से नामांकन शुरू हो गए हैं। हालांकि अक्सर ये देखा गया है कि नामांकन के आखिरी दिन ही पार्टियां अब अपने कैंडिडेट उतारती हैं, लेकिन ये अभी से तय हो गया है कि विधानपरिषद के चुनाव में सपा और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। ये मुकाबला 12वीं सीट के लिए होगा।

विधानसभा में सीटबल के आधार पर भाजपा 10 और सपा 1 सीट आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन, 12वीं सीट के लिए दोनों को कुछ वोटों का जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसे में इस जुगाड़ में कौन बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।

विधायक बनने के लिए कितने वोट चाहिए

सीधा फार्मूला तो ये है कि विधानसभा में जितने विधायक हैं उनकी सदस्य संख्या को चुनाव होने वाली सीटों से भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा, उतने वोट एक विधायक की जीत के लिए जरूरी हैं। इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में 402 विधायक हैं। चुनाव 12 सीटों पर होने हैं। ऐसे में अधिकतम 33.5 वोट एक विधायक के लिए चाहिए, लेकिन, प्रथम वरीयता के आधार पर जीत दिलाने के समय ये संख्या थोड़ी कम हो जाती है। इस चुनाव में 31 वोट जीत के लिए काफी होंगे।

इस चुनाव में भाजपा की स्थिति

उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के 310 विधायक हैं। इनके दम पर विधानपरिषद की 10 सीटें भाजपा आराम से जीत जाएगी। उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) की 9 सीटों को जोड़ दें तो उसके पास संख्या बल थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन तब भी ये उतनी नहीं होगी, जिससे एक और उम्मीदवार को जिताया जा सके। ऐसे में यदि भाजपा 11 विधायकों को जिताना चाहती है, तो उसे कुछ और वोटों का जुगाड़ करना पड़ेगा।

विधानसभा में सपा का हाल

सपा के 49 विधायक हैं। इसकी एक सीट पक्की है। एक सीट जीतने के बाद भी पार्टी के पास कुछ सरप्लस वोट बचेंगे, लेकिन ये इतने नहीं कि दूसरे उम्मीदवार जीता सके। ऐसे में सपा को भी कुछ और वोटों का जुगाड़ करना पड़ेगा।

बसपा और कांग्रेस

ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं, जिनके खाते में कोई सीट आती नहीं दिखती। इनके इतने विधायक ही नहीं हैं कि एक अदद सीट भी मिल सके, लेकिन यहीं फिर से वही राजनीति आकर खड़ी हो जा रही है, जो राज्यसभा के चुनाव के समय देखने को मिली थी। राज्यसभा जीतने के लिए बसपा के पास जरूरी वोट नहीं थे, लेकिन भाजपा के दम पर उसने एक सीट हासिल कर ली थी।

डा संदीप गर्ग आई.पी.एस. सीनियर पुलिस कप्तान जालंधर (देहाती) ने जानकारी देते हुए बताया कि तिथि 13/01/2021 को दविंदर कुमार अतरी पी.पी.एस.उप पुलिस कप्तान (स्थानीय), हरिंदर सिंह मान पी.पी.एस. उप पुलिस कप्तान सब डिवीजन आदमपुर और दफ्तर के स्टाफ को लोहड़ी के त्यौहार की बधाईयां दी गई और सारे समूह स्टाफ के साथ एक परिवार की तरह इस त्यौहार को मनाया गया।

पंजाब में अब और आसानी से मिलेंगी परिवहन सेवाएं- रजिया सुल्ताना

वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसंस बनाने के लिए 3500 से ज्यादा केन्द्रों के द्वारा किया जा सकता है आवेदन

500 सेवा केन्द्रों के बाद 'सांझे सेवा केंद्र' चलाने वाले 3 हजार उद्यमियों को भी किया अधिकारित

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब में वाहनों की रजिस्ट्रेशन करवानी और ड्रायविंग लायसंस बनाने अब और ज्यादा आसान हो गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुये परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने बताया कि प्रिवहन विभाग में ज्यादातर सेवाएं डिजिटल कर दी गई हैं और लोग घर बैठे ही इन सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों की रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी आवेदन-पत्र और ड्रायविंग लायसंस बनाने के इच्छुक घर बैठे ही वाहन और सारथी वैब ऐपलीकेशनों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सेवाएं www.parivahan.gov.in और www.punjabtransport.org वैबसाईट के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं।

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन्टरनेट का प्रयोग करना नहीं जानते या जिनके पास कंप्यूटर नहीं है उनके लिए प्रिवहन विभाग ने यह सुविधा सेवा केन्द्रों के द्वारा देनी शुरू की है। राज्य भर में 500 से ज्यादा सेवा केन्द्रों के द्वारा किसी भी कामकाज वाले दिन प्रति आवेदन सिर्फ 50 रुपए की अदायगी करके वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसंस बनाने के लिए आवेदन करने की सेवा प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि सेवा केन्द्रों के इलावा गाँवों में 3 हजार से ज्यादा ऐसे सांझे सेवा केंद्रों के द्वारा भी प्रति आवेदन 30 रुपए की अदायगी करके वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसंस बनाने के लिए आवेदन अप्लाई करने की सेवा ली जा सकती है।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की तरफ से लिए इस फैसले से यह दोनों अहम सेवाएं लेनी ज्यादा आसान और परेशानी रहित हो गई हैं।

प्रिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य प्रिवहन कमिशनर के साथ जुड़े पंजाब भर के सभी फील्ड दफ्तरों में हर साल 75 लाख से ज्यादा लोगों का आना-जाना है।

उन्होंने बताया कि 500 से ज्यादा सेवा केन्द्रों और 3 हजार से ज्यादा सांझे सेवा केंद्रों के द्वारा वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसंस बनाने के लिए आवेदन-पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की सेवा शुरू हो जाने से विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आयेगी और लोगों के दफ्तरों में चक्कर नहीं लगेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले सिर्फ 98 दफ्तरों के द्वारा वाहनों की रजिस्ट्रेशन कराने और ड्रायविंग लायसंस बनाने की आवेदन देने का प्रबंध था जोकि अब बढ़ कर 3500 से भी ज्यादा हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि गाँवों के सांझे सेवा केंद्रों को उपरोक्त काम के लिए अधिकारित करने से जहाँ यह केंद्र चलाने वाले नौजवानों की आय में विस्तार होगा वही लोग अपने घर के नजदीक ही प्रिवहन विभाग की सेवाएं बिना किसी परेशानी और मध्यस्थों रहित प्राप्त कर सकेंगे।

काबिलेगौर है कि यह केंद्र आवेदनकर्ता के लिए ऑनलाइन फार्म भरने, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन फीस की अदायगी आदि जैसी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। प्रिवहन विभाग के किसी भी दफ्तर में दस्ती फाइलें जमा करवाने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। आवेदन-पत्र ऑनलाइन ही जमा होते हैं। आवेदन ऑनलाइन अपलोड हो जाने के बाद आवेदनकर्ता के मोबायल पर इस संबंधी मेसेज भी आ जायेगा।

जिक्रयोग्य है कि सेवा केंद्र और सांझे सेवा केंद्र वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसंस बनाने के लिए सिर्फ आवेदन अप्लाई करेंगे जबकि इनको जारी सम्बन्धित सरकारी अथारिटी की तरफ से ही किया जायेगा।

पंजाब सरकार 16 जनवरी को हैल्थकेयर वर्करों के टीकाकरण के लिए पूरी तरह तैयार

टीकाकरण के लिए 20,450 वायल्स (कोवीशील्ड) प्राप्त हुई-बलबीर सिद्धू

सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा हैल्थकेयर वर्करों का डेटा किया गया अपलोड

चंडीगढ़/ब्यूरो

कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 16 जनवरी को 110 स्थानों पर हैल्थकेयर वर्करों (एच.सी.डब्ल्यू) के टीकाकरण के लिए पूरी तरह तैयार है। आज टीके की 20,450 वायल्स (शीशियाँ) प्राप्त हुई हैं और हर वायल में टीके की 10 खुराकें हैं जो लाभपात्री को 28 दिनों के अंतर में दो खुराकों में दी जाएंगीं।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि लम्बे इन्तज़ार के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब के ईपीआई अधिकारी द्वारा चंडीगढ़ हवाई अड्डे से कोवीशील्ड नामी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप प्राप्त की गई। उन्होंने बताया कि यह कोवीशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर तैयार की गई है और अब इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। इसके तीसरे पड़ाव के ट्रायलों का डेटा उपलब्ध है और इस वैक्सीन को इंग्लैंड में एमरजैंसी ऑथोराईज़ेशन के अंतर्गत लगाया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण की शुरूआत के लिए हरेक जिले में 5 स्थानों का चयन किया गया है, जहाँ हरेक स्थान पर 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि ज़िला अस्पताल एस.ए.एस. नगर और जी.एम.सी. अमृतसर में केंद्र सरकार के साथ दो सैशन साईट्स का सीधा प्रसारण/वैबकास्ट किया जायेगा।

वैक्सीन के लिए 'कोल्ड चेन' सम्बन्धी तैयारियों के बारे में विवरण देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय पर वैक्सीन को स्टेट वैक्सीन स्टोर, सैक्टर-24 में स्टोर किया गया है और बाद में इस वैक्सीन को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय, जिला और ब्लॉक वैक्सीन स्टोरों पर उपलब्ध करवाया जायेगा। हरेक टीकाकरण सैशन के प्रबंधन के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई और टीम की निर्धारित जिम्मेदारियों के मुताबिक पहला वैक्सीनेशन अधिकारी प्रवेश द्वार पर यह यकीनी बनाएगा कि सिर्फ़ योग्य वैक्सीनेटर ही दाख़िल हों, दूसरा वैक्सीनेशन अधिकारी कोविन ऐप पर लाभार्थियों का सत्यापन करेगा, तीसरा वैक्सीनेशन अधिकारी इंट्रामस्क्यूलर के तौर पर टीका लगाएगा, चौथा वैक्सीनेशन अधिकारी एईएफआई (टीकाकरण के बाद ऐडवर्स इफेक्ट) की निगरानी के लिए अवलोकन कक्ष में तैनात होगा और पाँचवाँ वैक्सीनेशन अधिकारी लाभार्थियों की भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता करेगा। इसके अलावा टीकाकरण प्रोग्राम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए टीम सुपरवाइजर और एईएफआई प्रबंधन केंद्र में नोडल अधिकारी भी तैनात किये गए हैं।

कानूनों की प्रतियां जलाकर किसानों ने मनाई लोहड़ी

दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नए कृषि क़ानूनों की प्रतियां जलाकर मनाया लोहड़ी का त्योहार।

पंजाब पुलिस की सांझ यूनिट ने प्रोजैक्ट विंटर वार्मथ के अंतर्गत बाँटे 'खुशहाली के छोटे पैकेट'

डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता ने गरीब परिवारों को बाँटे कंबल, भोजन और सर्दियों की जरूरी वस्तुओं वाले पैकेट

चंडीगढ़/ब्यूरो

सर्दी के इस ठंडे मौसम में गरीब परिवारों को गरिमा और हौसला देने के लिए दिल को छू लेने वाली पहलकदमी करते हुए आज पंजाब पुलिस के सांझ आऊटरीच कम्युनिटी विंग द्वारा प्रोजैक्ट विंटर वार्मथ की शुरूआत की गई।

डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी.जी.पी.) पंजाब दिनकर गुप्ता ने इस प्रोजैक्ट का उद्घाटन लोहड़ी के त्योहार के मौके पर पंजाब पुलिस हैडक्वाटर में आयोजित एक संक्षिप्त प्रोग्राम के दौरान गरीब परिवारों को 'खुशहाली के छोटे पैकेट' बाँट कर किया। इन पैकेटों में सर्दियों के लिए ज़रूरी वस्तुएँ जैसे कि कंबल, भोजन और अन्य चीज़ें शामिल हैं।

लोहड़ी के त्योहार के मौके पर गरिमापूर्ण बधाई देते हुए डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा, 'गुज़रा साल बहुत मुश्किलों भरा रहा। पंजाब पुलिस के बहादुर अफसरों ने राज्य के नागरिकों की सहायता के लिए पुरज़ोर यत्न किये। हमारी सांझ यूनिट महामारी के दौरान परिवारों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की मदद करने के मामले में अग्रणी रही और अब विंटर वार्मथ प्रोजैक्ट के ज़रिये इसमें और तेज़ी लाई जायेगी।

प्रोजैक्ट विंटर वार्मथ सांझ यूनिट की एक पहलकदमी है जिसको गरीब लोगों तक पहुँच बनाने के लिए पंजाब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) अथॉरिटी द्वारा सहायता दी गई है। बहुत से प्रमुख कॉर्पोरेट्स जैसे कि नैसले, मिसिज़ बैक्टर्स क्रीमिका, वर्धमान स्पैशल स्टील्स आदि इस नेक प्रयास में सहायता के लिए आगे आए और इस प्रोजैक्ट में खुलकर योगदान दिया है।

शुरूआती वितरण समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जबकि सांझ और पंजाब पुलिस की टीमों द्वारा लुधियाना, कपूरथला और अन्य जिलों में भी यह 'खुशहाली के छोटे पैकेट' बाँटे जा रहे हैं। पहले पड़ाव के दौरान राज्य भर में 11,000 के करीब पैकेट बाँटे जाएंगे।

एडीशनल डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (एडीजीपी) कम्युनिटी अफेअर्ज़ डिविजन् गुरप्रीत कौर दिओ ने कहा, 'प्रोजैक्ट विंटर वार्मथ सांझ की एक छोटी सी शुरूआत है, परन्तु हमें उम्मीद है कि हम आने वाले महीनों और सालों में इस पहलकदमी को और आगे लेकर जायेंगे। सांझ यूनिट कम्युनिटी सेवाओं पर केन्द्रित है और प्रोजैक्ट विंटर वार्मथ उन परिवारों के साथ नज़दीकी सम्बन्ध बनाने में मदद करेगा जिनकी हम सहायता करने की कोशिश करते हैं।'

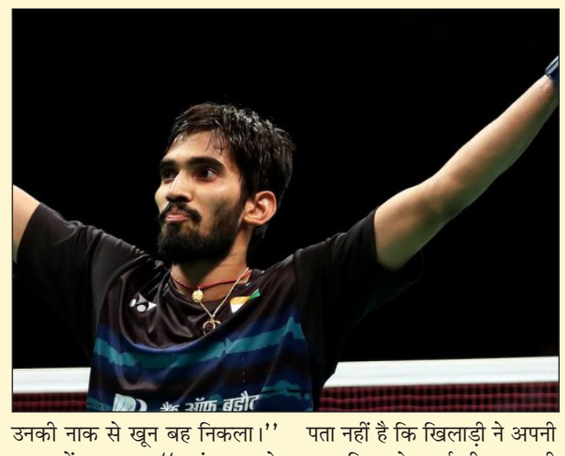

पंजाब सीएसआर अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) डा. सन्दीप गोयल ने पंजाब के सभी कॉर्पोरेट्स खासकर नैसले, मिसिज़ बैक्टर्स क्रीमिका, वर्धमान स्पैशल स्टील्स द्वारा प्रोजैक्ट विंटर वार्मथ में उनकी निरंतर सहायता के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य कॉर्पोरेटों ने गुप्त रूप में अपने सीएसआर फंडों के द्वारा योगदान दिया है।

ज़िक्रयोग्य है कि इस दौरान डीजीपी दिनकर गुप्ता द्वारा प्रोजैक्ट विंटर वार्मथ में योगदान देने वाले कॉर्पोरेटों को प्रशंसा पत्र भी सौंपे गए।

न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में भी शीर्ष दो स्थानों पर पहुंचने के करीब है। वह 70 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर ह

SPORTS PLANET
स्पोर्ट्स प्लैनट

चोटों की समस्याओं से घिरी भारतीय टीम ने ब्रिसबेन में शुरू किया प्रेक्टिस

ब्रिसबेन/ब्यूरो

चोटों की समस्याओं से जूझ रही भारतीय टीम ने बुधवार को यहां गाबा में अपने पहले अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया और उसे आस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में 11 फिट खिलाड़ियों को उतारने की उम्मीद है। सिडनी में तीसरे टेस्ट में पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अंतिम टेस्ट से बाहर हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब भी ट्रेनिंग सत्र के लिये भारतीय टीम के साथ हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कप्तान अजिंक्य रहाणे और अन्य को उनकी ट्रेनिंग किट के साथ देखा गया। बुमराह ने हालांकि अभ्यास करने के हिसाब से कपड़े नहीं पहने हुए थे और वह गेंदबाजी कोच भरत अरूण के साथ चर्चा कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, ''सिडनी में शानदार जज्बा दिखाने के बाद फिर एकजुट होने का समय। हमने गाबा में अंतिम टेस्ट के लिये अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।'' चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को नेट में गेंदबाजी करते हुए देखा गया। ऐसी उम्मीद है कि उन्हें मैच के लिये चुना जा सकता है क्योंकि हरफनमौला रविंद्र जडेजा अंगूठे में फ्रेक्चर के कारण नहीं खेलेंगे। तेज गेंदबाज शारदुल ठाकुर और हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर भी अभ्यास सत्र का हिस्सा थे। गाबा में अंतिम एकादश में बुमराह की जगह टी नटराजन या शारदुल को उतारे जाने की उम्मीद है, जिससे मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण नये स्वरूप में होगा।

मुख्य कोच रवि शास्त्री अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों के साथ थे और उन्होंने टीम के खिलाड़ियों से बातचीत भी की। वह सहयोगी स्टाफ के अपने साथियों के साथ भी बात करते हुए दिखे जिसमें अरूण के अलावा बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ और क्षेत्ररक्षण कोच आर श्रीधर शामिल थे। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार चोटों का सामना करना पड़ रहा है। टेस्ट श्रृंखला शुरू होने से पहले ही इशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार चोटों के कारण बाहर हो गये थे। पहले टेस्ट में बांह में चोट के कारण मोहम्मद शमी भी श्रृंखला के बाकी मैचों में हिस्सा नहीं ले सके जबकि उमेश यादव पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अंतिम दो टेस्ट से बाहर हो गये।

रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी दर्द के बावजूद भारत को सिडनी में ड्रा कराने में सफल रहे और अंतिम मैच में उनकी भागीदारी भी निश्चित नहीं है। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने सिडनी में 97 रन की पारी खेली लेकिन पहली पारी में लगी चोट के कारण विकेटकीपिंग नहीं कर सके थे।

कोविड टेस्ट के बाद किदाम्बी श्रीकांत के नाक से बहा खून, BWF ने की थाईलैंड ओपन के आयोजकों से बात

बैंकॉक/ब्यूरो

बैडमिंटन विश्व महासंघ ने बुधवार को कहा कि थाईलैंड ओपन के दौरान कोरोना जांच सुविधाजनक ढंग से सुनिश्चित करने के लिये वह आयोजकों के संपर्क में है इससे पहले भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत की नाम से टेस्ट के बाद खून बहने लगा था। दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी श्रीकांत की मंगलवार को कोरोना जांच हुई जिसके बाद उनकी नाक से खून बहने लगा। स्वास्थ्य अधिकारियों के रवैये से खफा श्रीकांत ने इसे 'अस्वीकार्य' बताया। बीडब्ल्यूएफ ने कहा कि आयोजकों ने खून बहने के कारणों की जानकारी दी।

इसने एक बयान में कहा, ''कई दौर की कोरोना जांच के बाद किदाम्बी श्रीकांत की नाक से खून बहने लगा था। उसका तीन बार नमूना लिया गया और वह तनाव में भी थे। शायद उसी वजह से उनकी नाक से खून बह निकला।'' बयान में कहा गया, ''जांच कर रहे दल ने उस समय उनकी नाक से खून निकलता नहीं पाया और उस समय श्रीकांत ने भी कोई शिकायत नहीं की थी।

इसके तीन से पांच मिनट बाद भारतीय टीम के एक अन्य सदस्य ने बताया कि उसकी नाक से खून बह रहा है।'' महासंघ ने कहा, ''यह पता नहीं है कि खिलाड़ी ने अपनी नाक टिश्यू से दबाई थी या उनकी नाक बह रही थी जिससे रक्त वाहिकाओं को चोट पहुंची।'' बयान में कहा गया कि आयोजकों से बात की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खिलाड़ियों और प्रतियोगियों की जांच सुविधाजनक और सुरक्षित माहौल में हो।

सिडनी टेस्ट की जोड़ी नंबर-1: हनुमा ने कहा- अश्विन ने मुझे बड़े भाई की तरह राह दिखाई, तभी मैच ड्रॉ करा सके

सिडनी/ब्यूरो

भारतीय ऑलराउंडर हनुमा विहारी ने रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट ड्रॉ कराया था।

दोनों ने छठवें विकेट के लिए रिकॉर्ड 43 ओवर खेलकर 62 रन की नाबाद साझेदारी की थी। इस पर हनुमा ने कहा कि पारी के दौरान अश्विन ने उन्हें बड़े भाई की तरह राह दिखाई थी। तभी दोनों के बीच इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो सकी।

ऑस्ट्रेलिया ने मैच में 407 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 5वां दिन खत्म होने तक 5 विकेट गंवाकर 334 रन बनाते हुए मैच ड्रॉ कराया। अश्विन और विहारी छठवें विकेट के लिए गेंद (259) के हिसाब से भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है।

तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही सीरीज अभी भी 1-1 की बराबरी पर है। 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में आखिरी टेस्ट खेला जाएगा।

आखिरी दिन बल्लेबाजी करना अच्छा अनुभव रहा

विहारी ने क्ष्टष्ट्ढ.ञ्चद्भ पर कहा, ''5वें दिन के आखिरी सेशन में बल्लेबाजी करना काफी शानदार अनुभव रहा। यह ठीक वैसा ही था, जैसा आप सपने में देखते हैं। मैं बहुत खुश हूं। अश्विन ने मुझे बड़े भाई की तरह गाइड किया। बल्लेबाजी के दौरान में काफी कुछ सोच रहा था, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि इस समय सिर्फ बॉल पर ही ध्यान दो।''

अश्विन ने 128 बॉल पर 39 और विहारी ने 161 बॉल पर 23 रन की पारी खेली थी।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor: ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.